खबरें फटाफट

राजीव कुमार होंगे नए वित्त सचिव

■ **भाषा, नई दिल्ली** : वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार को अब वित्त सचिव का पद दिया गया है। सुभाष चंद्र गर्ग के स्थान पर कुमार को वित्त सचिव बनाया गया। गर्ग को तबादले के बाद बिजली सचिव बनाया गया है।

धारा 370 को चुनौती, सुनवाई जल्द

■ **विस, नई दिल्ली** : जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाली धारा-370 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की गुहार लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे। याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय की ओर से जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच के सामने मामले को उठाया गया।

2 जी मामले में जल्द सुनवाई नहीं

■ **भाषा, नई दिल्ली** : दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला केस में पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा और अन्य को बरी करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर जल्दी सुनवाई से मंगलवार को इनकार कर दिया। जस्टिस ए.के. चावला ने कहा कि मामले की सुनवाई पहले से नियत की गई तारीख पर ही की जाएगी।

भ्रामक विज्ञापनों पर होगी कार्रवाई

■ **विस, नई दिल्ली** : अब कंस्यूमर्स की शिकायतों का निपटारा न केवल जल्द होगा, बल्कि भ्रामक विज्ञापन देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मंगलवार को कंस्यूमर प्रोटेक्शन बिल-2019 लोकसभा में पारित हो गया। अब इसे राज्यसभा भेजा जाएगा।

न्यूनतम मजदूरी वाला बिल पास

■ **विस, नई दिल्ली** : 'कोड ऑन वेजेज' यानी मजदूरी संहिता बिल मंगलवार को लोकसभा में पारित हो गया है। सरकार का कहना है कि इस बिल से जरिये वह सभी राज्यों में न्यूनतम मजदूरी निश्चित करना चाहती है।

10% कोटे पर सुप्रीम सुनवाई जारी

■ **विस, नई दिल्ली** : जनरल कैटिगरी के आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग को 10 फीसदी आरक्षण देने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई के लिए मामले को संवैधानिक बेंच को रेफर किया जाए या नहीं इस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। जस्टिस एस. ए. बोबडे की अगुआई वाली बेंच ने टिप्पणी की कि समानता के सिद्धांत में रिजर्वेशन अपवाद है।

राज्यपाल बोले, जम्मू में सब ठीक है

■ **एजेंसियां, श्रीनगर** : गवर्नर सत्यपाल मलिक ने मंगलवार को एक वाकये का जिक्र करते हुए जम्मू-कश्मीर की पूर्व की सरकारों को घेरा। उन्होंने कहा कि कश्मीर में राज करने वाले लोग यहां के निवासियों को इतने सपने दिखाते रहे कि एक साल तो मेरा शॉल वाला भी मुझसे पूछता रहा कि क्या हम आजाद हो जाएंगे? मैंने कहा कि तुम तो आजाद ही हो, लेकिन अगर तुम पाकिस्तान के साथ जाने को आजादी समझते हो तो चले जाओ, पर हिंदुस्तान को तोड़कर कोई आजादी नहीं मिलेगी।' राज्यपाल ने उन खबरों को अफवाह बताया, जिनमें कहा जा रहा है कि राज्य के विशेष दर्जे पर कोई बड़ा निर्णय होने वाला है। कहा कि राज्य में सब ठीक है।

विस, नई दिल्ली : लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी मंगलवार को तीन तलाक से जुड़ा विधेयक पास हो गया। AIADMK और जेडीयू के सदस्यों के राज्यसभा से बाहर जाने के बाद वोट के नंबर सरकार के पक्ष में आए गए। हालांकि कांग्रेस, वाईएसआर कांग्रेस और दूसरी कई पार्टियों ने तीन तलाक से जुड़े विधेयक का कड़ा विरोध किया। विपक्षी दलों के सदस्यों ने इसका मकसद मुस्लिम परिवारों को तोड़ना बताया। साथ ही तीन तलाक को अपराध की कैटिगरी में डालने पर आपत्ति जताई। बिल पास होने से पहले राज्यसभा इस पर जोरदार चर्चा हुई।

दो पार्टियां गईं बाहर, राज्यसभा के अंदर भी तीन तलाक बिल कबूल

विपक्ष ने कहा- बिल इस्लाम के खिलाफ

"पति को जेल भेजना घर के चिराग से घर को जलाने की कोशिश की तरह है। इस्लाम में शादी एक दीवानी समझौता है। सरकार इसे संज्ञेय अपराध क्यों बना रही हैं? **- गुलाम नबी आजाद, कांग्रेस**

■ तलाक देने वाले पति को जेल में डाल दिया गया तो वह जेल में रहने के दौरान अपनी पत्नी और बच्चों को गुजारा भत्ता कैसे दे पाएगा? **- डोला सेन, TMC**

■ कई पत्नियों को उनके पति छोड़ देते हैं। क्या सरकार ऐसे पतियों को दंड देने और ऐसी छोड़ी गई महिलाओं को गुजारा भत्ता देने के लिए कोई कानून लाएगी? **- जावेद अली खान, SP**

■ जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में कोई फैसला दे दिया है तो वह अपने आप में एक कानून बन गया है। ऐसे में अलग कानून लाने का क्या औचित्य है? **- माजिद मेनन, NCP**

■ सरकार को कश्मीर की लाखों विधवा महिलाओं की याद कब आएगी। आतंक और शोषण की शिकार इन महिलाओं को अब तक न्याय का इंतजार है। **- मीर मोहम्मद फैयाज, पीडीपी**

■ राजनीतिक सत्ता में भागीदारी से महिलाओं को अलग रखने वाली बीजेपी की ओर से मुस्लिम महिलाओं के हित में कानून बनाने की बात करना हास्यास्पद है। **- संजय सिंह, आप**

■ पीटकर जिन लोगों की हत्या कर दी गई क्या सरकार ने कभी उनकी पत्नियों के बारे में सोचा है? तीन तलाक विधेयक हिन्दू-मुसलमानों के बीच झगड़ा लगाने के लिए लाया गया है। **- दिग्विजय सिंह, कांग्रेस**

सरकार बोली- महिलाओं के साथ न्याय होगा

"एक जाने-माने जस्टिस आमिर अली ने 1908 में एक किताब लिखी है। इसके अनुसार तलाक-ए-बिद्दत का पैगंबर मोहम्मद ने भी विरोध किया है। **- रविशंकर प्रसाद, कानून मंत्री**

■ लोग कह रहे परिवार को कौन पालेगा? यह बात तो तमाम कानूनों पर लागू होती है। ऐसा में क्या परिवार की बात कहकर अपराधी को सजा न दी जाए। **- भूपेंद्र यादव, बीजेपी**

■ तीन तलाक से प्रभावित होने वाली करीब 75 प्रतिशत महिलाएं गरीब वर्ग की होती हैं। हम उन्हें (मुस्लिम समाज को) पीछे नहीं छोड़ सकते। **- रविशंकर प्रसाद, कानून मंत्री**

■ लोग तीन तलाक दे रहे हैं, मैं उनसे ये कहूं कि कोर्ट के फैसले को मढ़वा कर रख लो। फिर अवमानना का केस करो। पुलिस कहती है कि हमें ऐसे मामलों में कानून में अधिक अधिकार चाहिए। **- रविशंकर प्रसाद, कानून मंत्री**

■ तीन तलाक के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत मुस्लिम महिलाओं ने की थी। सरकार वास्तव में मुस्लिम महिलाओं का भला करना चाहती है, वह भी बिना किसी स्वार्थ के। **- भूपेंद्र यादव, बीजेपी**

■ देश की उन महिलाओं को खुशी मिलेगी जो तीन तलाक की कैद में हैं। इसमें धर्मनिरपेक्षता को खतरा होने की बात का कोई औचित्य समझ नहीं आता। **- संजय राउत, शिवसेना**

■ मैं मोदी सरकार का कानून मंत्री हूं, राजीव गांधी सरकार का नहीं। मैं मुस्लिम महिलाओं को बिलखता हुआ नहीं छोड़ सकता। **- रविशंकर प्रसाद, कानून मंत्री**

RTI बिल का रिहर्सल तीन तलाक पर काम आया

Manjari.Chaturvedi
@timesgroup.com

54 सांसद गैरमौजूद रहे सदन में तीन तलाक पर वोटिंग के दौरान

■ **नई दिल्ली :** राज्यसभा में एक हफ्ते के भीतर विवादास्पद आरटीआई बिल के बाद लगातार दूसरे अहम बिल तीन तलाक पर बहुमत साबित कर मोदी सरकार ने अपना दबदबा साबित कर दिया। सरकार ने आरटीआई बिल पर जो ड्रेस रिहर्सल की थी, तीन तलाक पर वह काम आई। आरटीआई बिल पास होने से ही सरकार के लिए तीन तलाक को पास कराने की राह आसान हो गई थी। अपने कुशल प्रबंधन से सरकार न सिर्फ बहुमत के नंबर जुटाए, बल्कि विपक्ष एकजुटता को तोड़ने में भी कामयाब रही। यह सरकार का फ्लोर मैनेजमेंट ही था कि सदन में सरकार-विपक्ष के 119-118 के अंतर को तीन तलाक बिल पर वह 99-84 में बदलने में कामयाब रही।

ऐसे मिली कामयाबी : सूत्रों के मुताबिक, पीएम मोदी और अमित शाह के इशारा मिलने के बाद सरकार की ओर से पीयूष गोयल, भूपेंद्र यादव और टीडीपी से आए सीएम रमेश ने विपक्षी एकजुटता में सेंध लगाई। कुछ धड़ों को अपनी तरफ साधने का काम किया। 240 के सदन में सरकार को बहुमत साबित करने के लिए 121 चाहिए थे। ऐसे में जहां सरकार का घटक दल घटक जेडीयू और उसके साथ रहने वाले एआईडीएमके (6+13) वॉकआउट कर गए, वहीं विरोध के चलते बीएसपी, टीडीपी और टीआरएस (4+2+6) वोटिंग से गैरमौजूद रहे। सदन से 54 लोगों को गैरमौजूद रहने से भी सरकार की राह आसान हुई।

पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर, बाबर रोड, बाराखंबा लेन, नई दिल्ली-110001
फोन: 011-23411411, फैक्स: 011-23472550,
CIN: L74899DL1998PLC093073
ई-मेल: investors@petronetlng.com
कम्पनी की वेबसाइट: www.petronetlng.com

नोटिस

एतद्द्वारा सेबी (सूचीयन उत्तरदायित्व तथा प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के प्रावधानों के अनुसरण में नोटिस दी जाती है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की बैठक बुधवार, 31 जुलाई, 2019 के बजाय बुधवार, 7 अगस्त, 2019 को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय अवस्थित वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर, बाबर रोड, बाराखंबा लेन, नई दिल्ली-110001 में पुनः निर्धारित की गयी है जिसमें अन्य बातों के अलावा 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार तथा इसको अनुमोदित किया जायेगा।

सेबी (प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग) रेगुलेशन, 2015, पीएलएल की प्रतिभूतियों में इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए आचार संहिता (पीएलएल का कोड) तथा स्टाक एक्सचेंजों द्वारा जारी सर्कुलर दिनांक 2 अप्रैल, 2019 के अनुसरण में, स्टाक एक्सचेंजों को पत्र दिनांक 28 जून, 2019 के माध्यम से यह सूचित किया गया था कि पीएलएल की प्रतिभूतियों में कारोबार के लिए ट्रेडिंग विंडो पीएलएल की संहिता के अनुसार सभी "इनसाइडर" के लिए 1 जुलाई, 2019 से 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणामों को एक्सचेंजों में दाखिल करने तथा सामान्य रूप से उसके उपलब्ध होने के 48 घंटे बाद तक बंद रहेगा।

उपरोक्त के आलोक में, पीएलएल की प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विन्डो 1 जुलाई 2019 से 9 अगस्त 2019 (1 जुलाई 2019 से 2 अगस्त 2019 के स्थान पर) (दोनों दिन सहित) की अवधि के दौरान बंद रहेगी। ट्रेडिंग विन्डो शनिवार, 10 अगस्त, 2019 (3 अगस्त, 2019 के स्थान पर) को पुनः खुलेगी। तद्नुसार, यह सभी संबंधितों (जिनके लिए यह उपरोक्त कोड लागू है) से अनुरोध किया जाता है कि ट्रेडिंग विन्डो की बंद अवधि के दौरान पीएलएल की प्रतिभूतियों में ट्रेड नहीं करें।

यह जानकारी कंपनी की वेबसाइट www.petronetlng.com तथा स्टाक एक्सचेंजों की वेबसाइट जहां पर कंपनी सूचीबद्ध है अर्थात www.nseindia.com तथा www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

कृते पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड
हस्ता./-
(राजन कपूर)
सीजीएम तथा वाइस प्रेसिडेंट-कंपनी सेक्रेटरी

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 30 जुलाई, 2019

कांग्रेस-NCP के 4 MLA का इस्तीफा

■ **भाषा, मुंबई :** महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और एनसीपी में इस्तीफों का दौर जारी है। मंगलवार को दोनों दलों के 4 विधायकों ने रिजाइन कर दिया। इनमें कांग्रेस के कालिदास कोलाम्बकर, एनसीपी के शिवेंद्र सिंह भोसले, वैभव पिचाड और संदीप नाइक शामिल हैं। चारों ने स्पीकर हरिभाऊ बागड़े से मुलाकात कर अलग-अलग इस्तीफा सौंपा। ये सभी बुधवार को बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। वैसे एनसीपी प्रमुख शरद पवार के करीबी माने जाने वाले मधुकर पिचाड के बेटे वैभव और कांग्रेस के कोलम्बकर पहले ही बीजेपी का दामन थामने का ऐलान कर चुके हैं।

आजम की जौहर यूनिवर्सिटी में मिलीं चोरी की किताबें

Shadab.Rizvi@timesgroup.co

■ **मेरठ :** दो दर्जन से भी अधिक मामलों में फंसे एसपी के वरिष्ठ नेता और सांसद आजम खान की मुश्किलें और बढ़ती दिख रही हैं। मंगलवार को रामपुर में उनकी जौहर यूनिवर्सिटी पर पुलिस प्रशासन ने छापा मारा। यहां की लाइब्रेरी से पुलिस ने रामपुर के ऐतिहासिक मदरसा आलिया से चोरी हुईं 100 से ज्यादा किताबें बरामद की हैं। पांच कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया है।

पुलिस ने किसानों की जमीन पर कब्जा कर यूनिवर्सिटी बनाने के मामले की भी जांच की है। इस केस में आजम खान और उनके सहयोगी आले हसन आरोपी हैं। आले हसन के खिलाफ लुक आउट

नोटिस जारी हुआ है, जबकि आजम को प्रशासन ने भूमाफिया घोषित किया है।

आजम के बेटे पर FIR : आजम खान के विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम भी दो जन्मतिथि के मामले में फंस गए हैं। उनके खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना का आरोप है कि अब्दुल्ला ने पासपोर्ट बनवाने के लिए गलत जानकारी दी है।

टीपू सुल्तान जयंती पर कर्नाटक में रोक

■ **भाषा, बेंगलुरु :** कर्नाटक में नई बीजेपी सरकार ने टीपू सुल्तान के जयंती समारोह पर रोक लगा दी है। सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि प्रदेश में टीपू जयंती मनाने की कभी परंपरा नहीं रही है और इसलिए हमने इसे नहीं मनाने का फैसला किया। कांग्रेस ने राज्य सरकार के फैसले का विरोध करते हुए कहा कि यह बीजेपी के भगवाकरण की राजनीति का असर है। वह अपने स्तर पर जयंती मनाती रहेगी।

TIMES HOLIDAYGUIDE